



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry  
Government of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन. एच. बाइपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन - 682 025, भारत

प्रचार-प्रदर्शन /0008/2022-प्रचार

21 जुलाई 2022

### परिपत्र

## एमएआई सहायता योजना एवं दिशा-निर्देशों के तहत 'वल्ड फूड मोस्को 2022' में स्पाइसेस बोर्ड की सहभागिता

\*\*\*

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एमएआई सहायता योजना एवं दिशा-निर्देशों के तहत मोस्को, रूस में 20 से 23 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित होने वाले 'वल्ड फूड मोस्को 2022' में भाग ले रहा है। स्पाइसेस बोर्ड के स्टाल में पंजीकृत मसाला निर्यातकों की सहभागिता आमंत्रित कर रहा है। बोर्ड सभी निर्यातकों को सामान्य क्षेत्र सहभागिता प्रदान करता है। सहभागिता के लिए शर्तें नीचे सूचीबद्ध हैं।

- 1) चयन पहले आओ - पहले पाओ आधार पर होगा। इच्छुक निर्यातक अपना निरोध ई-मेल द्वारा 29 जुलाई 2022 को सायं 5.00 बजे या उससे पहले [publicity.sb-ker@gov.in](mailto:publicity.sb-ker@gov.in) पर और प्रतिलिपि [prathyush.tp@nic.in](mailto:prathyush.tp@nic.in) पर भेजेंगे।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति स्थान के आबंटन की गारंटी नहीं देती है। जहाँ भी लागू हो, स्थान का आबंटन उपलब्धता और मेला आयोजन प्राधिकरणों से अनुमोदन के आधार पर होगा।
- 3) बोर्ड सभी मेलों में निर्यातकों को, स्पाइसेस बोर्ड पविलियन के अधीन भाग लेने वाले निर्यातकों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत काउंटर आबंटित करने का प्रयास करेगा।
- 4) चयनित निर्यातक को एक ग्लास काउंटर टेबल / दो कुर्सियाँ / प्रावरणी नाम / एक ब्रांडिंग विकल्प / ब्रोशर स्टैंड आदि प्रदान किया जाएगा।
- 5) बोर्ड सहभागीदारी की व्यवस्था केवल बोर्ड के स्टॉल में करेगा। यात्रा, विसा, बोर्डिंग एवं लोडिंग, स्थानीय परिवहन आदि संबंधित सभी व्यवस्थाएँ और सभी अन्य व्यय सहभागी निर्यातक द्वारा वहन किया जाएगा।
- 6) एक बार निर्यातक सहभागिता के लिए चयनित होने पर प्रदर्शक पास कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल दो पदधारियों को दिया जाएगा।

- 7) निर्यातक स्पाइसेस बोर्ड योजना के द्वारा मेले में भाग लेने के लिए किफायती हवाई किराए की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कर सकता है। सामान्य श्रेणी के लिए प्रतिवर्ष सहायता प्रति वर्ष हवाई किराए की लागत का 50% बशर्तेकि अधिकतम 1.50 लाख रुपये होगी और अ जा/अ ज निर्यातक, एफपीओ निर्यातक, उत्तरपूर्व क्षेत्र (सिक्किम और दार्जीलिंग सहित) और अन्य हिमालयी राज्य/ जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, आईटीडीपी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राज्य एवं द्वीप(अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश) के लिए प्रति वर्ष हवाई किराए की लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम 2.25 लाख रुपए होगी। यह योजना उपलब्ध करने के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
- 8) बोर्ड सहभागीदारी के निबंधन और शर्तों पर अनिवार्य बदलाव लाने का अधिकार रखता है। स्थान का आबंटन और सहभागीदारी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 9) इच्छुक निर्यातक अपना ई-मेल अनुरोध निम्नलिखित फॉर्मेट में साझा करेंगे;

कंपनी का नाम (सीआरईएस के अनुसार)	सीआरईएस पंजीकरण संख्या	पता	कंपनी प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम	मोबाइल नंबर

स्थान: कोच्ची

[निदेशक] [विपणन]